हैं ? (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह : ऐसा करने से इनको वोट नहीं मिलेंगे। (व्यवधान)

श्री मनुभाई पटेल : क्या चापलूसी करने से वोट मिलेंगे ? (व्यवधान)

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, इनको समझा दीजिए कि सीज़र्स वाइफ शुड ए बिय़ाव ससपिशन ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह प्राइम मिनिस्टर के इन्ट्रेस्ट में भी है कि वह आकर सवालों का जवाब दें, क्योंकि लोगों को शक है कि इस बारे में फेवरिटिज्म हुआ हैं ।

Foreign Exchange for Small Car Project

*31. SHRI MADHU LIMAYE : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTRENAL TRADE be pleased to state :

(a) what is the amount of foreign exchange that is likely to be sanctioned for the small car project of Shri Sanjay Gandhi ;

(b) whether the foreign exchange granted to the companies supplying sub-assemblies, parts and equipment to the small car project will also the treated as foreign exchange outlay on the small car project itself ; and

(c) if not, the reasons for not including this foreign exchange outlay as outlay on the small car project ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI DINESH SINGH) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The letter of Intent for the manufacture of passenger cars has been granted to Shri Sanjay Gandhi subject to the condition that no foreign exchange expenditure will be involved either on foreign collaboration or for the import of capital goods, components or raw materials except in accordance with Government's normal policy, where import of raw materials nomally available in the country would be considered on request, in the event of such raw materials being in temporary short supply.

(b) and (c). There are a large number of firms in the Private Sector manufacturing automobile ancillary items. While some of the ancillary manufactures are, at present; manufacturing such items with indigenous materials, some others require foreign exchange either for the import of components or raw materials. Such ancillary manufacturers are being assisted with foreign exchange in accordance with their approved phased manufacturing programmes. The foreign exehange allocated to such manufacturers varies from unit to unit and product to product. Vehicle manufacturers purchase their requirments of ancillary items from thc indigenous ancillary manufacturers, wherever available, and in calculating the indigenous content achieved by the vehicle manufacturers, the ancillary items obtained by them from the indigenous ancillary manufactusers are treated as indigenous. In the light of the accepted practice, the foreign exchange allocated to the indigenous manufacturers of automobile ancillaries for the manufacture of sub-assemblies, parts, components and equipment to be supplied to proposed car project under reference are not to be treated as foreign exchange outlay on that car project.

Issue of Letters of Intent for Manufacture of Small Car

+

*34. SHRI RABI RAY :
SHRI SRADHAKAR SUPAKAR :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that letters of intent have been issued by

the Ministry to Shri Sanjay Gandhi and Shri Madan Mohan Rao for manufacture of small cars in private sector ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is also a fact that Government have issued licences to one of them and if so, the details thereof ; and

(d) the estimated selling price of the car ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE (SHRI DINESH SINGH) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) The letters of intent have been granted to Shri Sanjay Gandhi and Shri M. Mohan Rao for the establishment of new undertakings for the manufacture of cars for an annual capacity of 50,000 Nos. and 25,000 Nos. respectively subject to the following conditions :

(i) No foreign collaboration or foreign consultancy arranegments will be permitted.

(ii) No. imports of capital goods will be allowed.

(iii) No imports of components or raw materials will be allowed except in cases where raw materials normally available in the country being in temporary short supply may with the be imported in accordance have to import policy prevailing at that time.

(iv) Before the letter of intent is converted into a licence, prototype (s) will be developed and got tested and approved for roadworthiness by an authority approved for the purpose by Government,

(c) No, Sir.

(d) The estimated ex-factory selling prices of the cars indicated by the two parties in their industrial licence applications are as under :

Shri Sanjay Gandhi	—	about Rs. 7,000/-
Shri Madan Mohan Rao	—	Rs. 8000/-

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इन प्रश्नों के उत्तर में दिये गये स्टेटमेंटस को पढ़ दें । उनकी आवाज़ बहुत मधुर है । उससे अच्छा असर पड़ता है ।

MR. SPEAKER : The statement has been laid on the Table. The hon. Member has got it.

श्री मधु लिमये : सब माननीय सदस्यों के पास वे स्टेटमेंटस नहीं हैं ।

श्री रवि राय : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस लिए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ दिया जाये ।

MR. SPEAKER : We do not want to depart from the practice.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : On a point of order. The Prime Minister happens to be the Chairman of the Licensing Committee and this question relates to the Licensing Committee's action. Therefore, as Chirman of the Licensing Committee the Prime Minister must be present here.

MR. SPEAKER : No, no.

SHRIMATI TARKESHWARI SINHA : Otherwise, this question should be held over till the Prime Minister is in the House.

SHRI BALRAJ MADHOK : I support the suggestion. She must be here.

MR. SPEAKER : No, no.

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री के इस बयान की ओर गया है कि मुल्क में दो, सवा दो करोड़ नौजवान बेकार हैं, उन को प्रोत्साहित करने के लिए मैं अपने बाबा को लाइसेंस देना बहुत ज़रूरी समझती हूं ? प्रताप सिंह कैरों, कृष्णवल्लभ सहाय और बीजू पटनायक आदि लोगों ने अपने रिश्तेदारों को जो रियायतें दीं, उन को ले कर जांच कमीशन बैठे और उनको दोषी पाया गया और उसके फलस्वरूप उन को सत्ता से हटना पड़ा । प्रधान मंत्री तो खुल कर कह रही हैं कि मैं अपने लड़के को लाइसेंस दूंगी । क्या मंत्री महोदय इस बात का खुलासा करेंगे कि.....(**व्यवधान**) मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निर्णय करेगी कि जो सत्ता में लोग हैं,.....(**व्यवधान**) कान्ति करे, वह बुरा है और इन का बाबा करे, वह अच्छा है - वह क्या तरीका है ?

क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि - - - (**व्यवधान**) जीने के लिए हेनरी फोर्ड बनने की जरूरत नहीं है उनको । उनको किसी साइकिल फ़ैक्टरी में मिस्त्री लगा दीजिए । (**व्यवधान**) भ्रष्टाचार का वह जो नंगा प्रदर्शन हुआ है, उस को ले कर देश की और लोकतंत्र की बेइज्ज़ती हुई है । क्या मंत्री महोदय घोषणा करेंगे कि किसी भी मंत्री या प्रधान मंत्री के नजदीकी रिश्तेदार को छोटी कार बनाने का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने किसी एक वक्तव्य का ज़िक्र किया, जिस में उन के मुताबिक प्रधान मंत्री ने कहा है कि चूंकि बहुत से बेकार नवयुवक हैं, इस लिए मैं अपने लड़के को लाइसस देना चाहती हूं, या मैने दिया है । ऐसा कोई वक्तव्य मैं ने नहीं देखा है । (**व्यवधान**)

श्री मधु लिमये : मैं मंत्री महोदय के साथ अन्याय नहीं करना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह बयान देखा है ।

श्री रवि राय : अगर अध्यक्ष महोदय इजाज़त दें, तो हम दस मिनट में लाइबरेरी से वह बयान मंगवा दें । (**व्यवधान**)

श्री हरदयाल देवगुण : क्या मंत्री महोदय यह तो जानते हैं कि वह प्रधान मंत्री का लड़का है ? या वह यह भी नहीं जानते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रधान मंत्री तो एक स्थान है, प्रधान मंत्री का लड़का नहीं होता, श्रीमती इन्दिरा गांधी का लड़का है.....

SHRI UMANATH : What awkward job you have taken up we sympathise with you.

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने जो कुछ उल्लेख किया, उसका मतलब यह था कि लाइसेंस देने में कोई रियायत की गई है । मैं माननीय सदस्य से आप के ज़रिये यह कहना चाहता हूं कि इस लाइसेंस में कोई रियायत नहीं की गई है ... (**व्यवधान**) ... माननीय सदस्य अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो मैं कहूं, या वह खुद कहना चाहते हैं तो पहले उन की बात सुनूं—दोनों एक साथ नहीं चल सकते... मैं अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक रियायत की बात है, माननीय सदस्य बिलकुल ठीक कहते हैं कि किसी भी मंत्री, खास कर प्रधान मंत्री के लड़के या रिश्तेदार के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए । इस में मिनिस्टर के सम्बन्धी का ही सवाल नहीं है, किसी के साथ भी कोई गलत तरीके से रियायत नहीं होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस लाइसेंस को देने में किसी के साथ कोई रियायत नहीं की गई है । इस में किसी भ्रष्टाचार का सवाल नहीं है, ज़ाबते से जो हमारा नियम है उसी के अनुसार यह लाइसेंस दिया गया है ।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने पूछा था कि क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि किसी भी मंत्री के रिश्तेदार को भविष्य में लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे, ताकि भ्रष्टाचार रुक सके ?

श्री जेनश्वर मिश्र : अगर दिये जायेंगे तो वे मंत्री इस्तीफा दे देंगे।

SHRI PILOO MODY : A person can always choose between Ministership and industry.

SHRI DINESH SINGH : I am quite sure Mr. Mody will choose the latter, but the question really is.....

अध्यक्ष महोदय : आप पीलू मोदी को मत छेड़िये।

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, वह बाहर मुझसे कहते हैं कि आप मेरे बारे में जब कुछ नहीं कहते हैं तो लगता है कि मेरा नोटिस नहीं लिया गया।

अध्यक्ष महोदय, कोई चीज रियायत से हो या गलत तरीके से हो—तो यह बात ठीक नहीं है। लेकिन चाहे मिनिस्टर या माननीय सदस्यों के लड़के हों या रिश्तेदार हों, अगर उन को काम करने से इस तरह से रोका जायेगा तो वे अपनी जिन्दगी किस तरह से बसर करेंगे। फिर तो जिस भ्रष्टाचार की बात माननीय सदस्य कहते हैं, उन की शुरूआत हो जायेगी।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो छोटी कार बनाई जायेगी उस के लिए यह शर्त रखी गई है कि कोई भी सामान आयात न किया जाय। लेकिन मैं जानता हूं—इन का इरादा है कि अधिकतर सामानों की सब-असम्बलीज़ को इकट्ठा कर के कार बनाई जाय। इस तरह से जो सब-असेम्बलीज़ बनाने वाले लोग हैं, उन को एक्सचेन्ज मिलेगा और वह एक्सचेन्ज संजय गांधी के खाते में नहीं दिखाया जायगा। इस सम्बन्ध में इन का यह वाक्य बिल्कुल साफ है, मैं इसे पढ़ देता हूं, शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है।

"In the light of the accepted practice, the foreign exchange allocated to the indigenous manufacturers of automobile ancillaries for the manufacture of sub-assemblies, parts, components and equipment to be supplied to proposed car project under reference are not to be treated as foreign exchange outlay on that car project."

मंत्री महोदय ने जिस ईमानदारी से इस बात को कहा है, क्या उसी ईमानदारी से वह कहेंगे कि संजय गांधी को जो लेटर कर आफ इन्टेन्ट दिया गया है और बाद में जो लाइसेंस देंगे, उस के अन्दर कितने पार्ट्स वे स्वयं बनायेंगे जिन में आयातित सामान का इस्तेमाल नहीं होगा और कितने पुर्जे वह दूसरी कम्पनियों से लेंगे जिन में आयातित माल रहेगा ? मुझे परसेन्टेज में भी और पार्ट्स में भी साफ जवाब चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह परसेन्टेज में जवाब देते हैं। जैसे इस में शल की बात करेंगे तो स्टील शीट को मोड़ कर शल बनेगा। इस में डेढ़-दो हजार पार्ट्स का इस्तमाल होता है—इस लिए मंत्री महोदय इस सदन को साफ साफ अवगत करायें कि कितने पुर्जे देशी माल से संजय गांधी अपने कारखाने में बनायेंगे और कितने पुर्जे वह बाहर से लेंगे जिन में आयातित सामान रहेगा? मेहरबानी करके साफ उत्तर दें ताकि रवि राय के पत्र का जो उन्होंने जवाब दिया है, वह कितना बोगस है, उस का सदन को पता लग जाय।

•

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो सामान बनता है, सबसे पहले हमें उसके नियम को देखना चाहिए आज हम यह कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पार्टस—ऐन्सी-

लियरी हिस्से - बड़े उद्योगों के बजाय छोटे उद्योगों में बनें, चाहे मोटर का कारखाना हो, या दूसरी चीजों का कारखाना हो, उनके एन्सीलियरी पार्ट्स लघु उद्योगों के क्षेत्र में बनें, यहां तक कि जो हमारा पब्लिक सैक्टर में मोटर का प्रोजैक्ट है, उस के लिये भी हम इसी कोशिश में हैं उसके जितने भी हिस्से हैं, हो सके तो उन को लघु उद्योगों के क्षेत्र में बनाया जाय। जब संजय गांधी अपनी मोटर बनायेंगे तो मैं आशा करता हूं कि वह भी हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र का इस्तेमाल उसी प्रकार से करेंगे.....(व्यवधान)....

जहां तक मोटर के पुर्जों का सम्बन्ध है जो पुर्जे इस देश में बनते हैं, उन में कुछ न कुछ इम्पोर्टेड—कन्टेन्ट अभी भी रहता है, जिस को हम धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ऐसे बहुत से पार्टस हैं जो हमारे लघु उद्योगों में बन रहे हैं और उनको सभी मोटर वाले खरीदते हैं, संजय गांधी के लिए इस में कोई विशेष इन्तजाम नहीं किया जा रहा है। जैसे स्टार्टर में इस समय 8 फीसदी इम्पोर्टेड कन्टेंट्स हैं, जैनरेटर में 5 फीसदी, हैड-लैम्प्स में 1.5 फीसदी, डिस्ट्रीब्यूटर में 7.5 फीसदी, फ्लेशर में 1 फीसदी, वाइपर में 4.5 फीसदी स्विच-सालेनाइट में 5 फीसदी, आल्टरनेटर 5 फीसदी, इलैक्ट्रिक-हार्न में 5 फीसदी, बेक्स में 5 फीसदी, स्टीयरिंग गीयर में 10 फीसदी, तो इस तरह के जो पाट्रस या कम्पोनेन्ट्रस हैं, उन में इम्पोर्टेड-कन्टेन्ट्स हैं, इन को सभी खरीदते हैं।

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, अभी प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री जी कह रहे थे कि संजय गांधी जो कार बनाने वाले हैं उस की एस्टीमेटेड कास्ट एक्स-फैक्टरी 7 हजार रुपये हैं और मदन मोहन राव जो कार बनाने वाले हैं उसकी एस्टीमेटेड एक्स फैक्टरी कास्ट 8 हजार रुपये हैं। मैं मंत्री महोदय में जानना चाहता हूं कि जिस देश में करीब 7-8 करोड़ लोग बेकार हैं, 30 करोड़ लोगों को दिन-प्रति दिन भरपेट भोजन खाने को नहीं मिलता है, क्या उस देश की योजना का यह तकाजा है कि सरकार स्माल-कार बनाने के लिए इतना प्रयत्न करे और प्रधान मंत्री खुद के लड़के को लाइसेंस देने के लिए आम बयान दे रही हैं।

क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आधुनिकीकरण ने इस देश की सारी योजना को चौपट कर रखा है, देश वासियों के पीने के लिए पानी नहीं है, खाना मकान गरीबों को नहीं मिला हैं इसलिए क्या सरकार इस सारी स्कीम को कैंसिल करेगी ? दूसरे प्रधान मंत्री का यह आम बयान आया है कि उनका लडका बहुत एडवेंचरस है इस लिए उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, हम मांग करते हैं कि क्या दिनेश सिंह जी यहां पर एलान करेंगे कि प्रधान मंत्री हस्तीफ़ा दें। हम प्रधान मंत्री के ऊपर सीध भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। *(Interruption)*

MR. SPEAKER : Order, order. When you put a question, ask your supplementary question, if you want to censure the Government, it should be done through a regular motion.

श्री रवि राय : मंत्री जी हमारे प्रश्न का जवाब दें।

श्री दिनेश सिंह : आपने सवाल के पहले हिस्से में कुछ बुनियादी बातें उठाई हैं। आपकी आज्ञा से मैं उनका विस्तार से जवाब दूंगा। सबसे पहले, जहां तक कि छोटी कार के प्रोजेक्ट का सवाल है, 1966 में इसी सदन में उसके बारे में बयान दिया गया। उस समय श्री संजीवैया मिनिस्टर थे। ऊन्होंने 1966 में इसके बा रे में अपने वक्तव्य में जो कहा था उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ देता हूं।

"In the meantime, we shall also examine further whether it is feasible

to set up indigenous capacity in the private sector on the basis that no import of foreign items is involved. I would request the house to bear with me a little longer."

उस समय श्री संजय गांधी इस क्षेत्र में नहीं थे और उस वक्त से यह बात चल रही है। (व्यवधान) अब कठिनाई यह है कि जो बातें माननीय सदस्य कहलाना चाहते हैं वह जब खिलाफ़ पड़ती हैं तो उनको सुनना नहीं चाहते हैं।... (व्यवधान) .. तो उसके बाद इसके बारे में फिर एक वक्तव्य इसी सदन में दो जून, 1967 को दिया गया और उस वक्त भी यही बात कही गई थी जबकि उस वक्त भी श्री संजय गांधी का कोई लाइसेंस नहीं आया था। उस समय फखरूद्दीन साहब ने यहां पर अपना बयान दिया था कि जो इन्डीजिनस नो-हाऊ से बिना इम्पोर्ट के मोटर बनाना चाहें, हम उनको मोटर बनाने की इजाजत देंगे। उसके बाद आपकी इजाजत से 10 अगस्त, 1970 को मैं ने यहां पर बयान दिया था जिस में मैंने कहा था कि एक पापुलर कार हम पब्लिक सेक्टर में बनायेंगे। उस वक्त भी हमने कहा था कि जो लोग इन्डिजिनस नो-हाऊ से बिना इम्पोर्ट के मोटर बना सकते हैं, हम उनको इजाजत देंगे। 1966 में यह कहा गया था कि जो लोग इस तरह की मोटर बना सकें वे अवेदन-पत्र दें। फिर कुछ आवेदन-पत्र आये भी लेकिन उनमें से कोई भी इंडिजिनस नो-हाऊ से, बिना फारेन कोलाबोरेशन या बिना इम्पोर्ट के नहीं था। बाद में भी कुछ आवेदन-पत्र आते रहे लेकिन वे भी बिना इम्पोर्ट के या बिना फारेन कोलाबोरेशन के नहीं थे। तो हमने यह कोई नयी चीज या नयी पालिसी नहीं बनाई है या हम श्री संजय गांधी के लिए कुछ खास कर रहे हैं, यह मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दें। ... (व्यवधान)... सरकार की यह नीति पिछले कई सालों से चली आ रही है और उसी के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। इस सदन की पिछली बैठकों में दो सवालों, अनस्टार्ड क्वेश्चन्स नं० 4740 और 4747 का जवाब दिया जा चुका है जिसमें ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। बातें कोई नयी नहीं हैं। लेकिन माननीय सदस्य जिस रूप में उनको रखना चाहते हैं वह तो उनकी बात है—उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इस लाइसेंस को देने में कोई भी हमने रियायत श्री संजय गांधी की तरफ नहीं दिखाई है। जो एक जान्ते से काम होता है उसी जान्ते से वह हुआ है। उस को राजनीतिक ढंग से जिस तरह के लोग रखना चाहें, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जान्ते से इसमें कोई भी गलत बात नहीं हुई है ? ... (व्यवधान) ...

श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मंत्री महोदय का जवाब सुनने से मुझे ऐसा लगा कि मैं अमरीका के उद्योग मंत्री को सुन रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह 8 हजार या 7 हजार की कार हिन्दुस्तान में कितने लोग खरीदने वाले हैं ? यह विलास की सामग्री है इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या विलास की सामग्री के लिए लाइसेंस देना बन्द करेंगे ? आखिर इस देश में इस कार को कितने लोग खरीदने वाले हैं ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि आज जबकि मोटरें काफी कीमत पर मिलती हैं फिर भी इतनी बड़ी वेटिंग लिस्ट हैं कि पांच साल तक लोगों को इन्तजार करना पड़ता है। ...(व्यनधान)... आज हमारे देश में प्रगति हो रही है, औद्योगिक प्रगति हो रही है और उस प्रगति के साथ लोग चाहते हैं कि उनके पास साधन हो ताकि अपनी प्रगति को और बढ़ायें। माननीयय सदस्य गरीबों का बड़ा जिक्र कर रहे थे लेकिन क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि जो गरीब हैं वे इस देश में हमेशा गरीबी में ही रहें।.....(व्यवधान).....

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : There are other printed names in Question 34. I must finish them before I call others. Mr. Supakar.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : The question of setting up a small car project in the public sector is hanging fire for quite a number of years. But as soon as the application from the private sector comes up, we find the licensing committee of the Government of India has almost immediately issued a licence. I want to have a comparative study of the percentage of the foreign exchange component in the public sector projects, specially the one in which the Government of Mysore was interested, which has been under the consideration of the Planning Commission for a number of years and the foreign exchange component involved in the new project, just now mentioned by the hon. Minister.

SHRI DINESH SINGH : I take it that the hon. member is referring to as the Mysore project is the project of the Mysore State Industries Investment and Development Corporation.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Or any other project in the public sector which has been submitted to the Planning Commission and the Government of India.

SHRI DINESH SINGH : I am not aware of what the Planning Commission is doing. We are concerned here with the licensing. We had received a proposal from the Mysore State Industries Investment and Development Corporation which had proposed to manufacture a car in collaboration with a foreign firm. As I mentioned, we are not allowing collaboration. There was no proposal from the Mysore State Industries Investment and Development Corporation for the manufacture of an indigenous car.

SHRI K. LAKKAPPA : The hon. Minister has now made an insinuation against the Mysore State because that State has all along been urging the use of only indigenous technical know-how available in that State. In Mysore electricity is available in abundance and so also raw materials. In the light of that I would like to ask a question to the Minister. The small car project is still a dream because monopoly houses which has been manufacturing cars have been pressurizing this Government not to allow a small car projeot, either in the public or private sector. Will the government take a final decision at once to start the munufacture of small car in the public sector and put an end to this controversy ?

SHRI DINESH SINGH : As I mentioned earlier, I am not awaie of any application from the Mysore Government for permission to manufacture car on the basis of indigenous know-how without any import. If the hon. Member is able to persuade the Mysore Government to sent such an application, I will be glad to recommend it to the licensing committee. So far ss the second part of the question is concerned, as I mentioned in this House on the 10th of August 1970, a decision has already been taken to munufacture a popular car in the public sector. We have invited collaboration from foreign companies and we have already received some offers. We have given time till the end of November to submit collaboration proposals and I hope early next year we will be able to finalise the callaboration arrangement.

SHRI K. LAKKAPPA : The monopoly houses have been pressurising this government for a very long time and that is why the manufacture of the small car has been delayed by this government. That point has not been answered.

SHRI DINESH SINGH : As the House is very well aware, this Government does not get pressurized.

श्री बलराम मधोक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा है कि इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह तथ्य नहीं है कि दिल्ली के एक नौजवान ने मुकम्मिल तौर पर इंडिजिनस कार बनाई हैं जिसको कि वह चलाकर पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी आपको दिखाने के लिए

तैयार हैं ? वह कार पांच साढ़े पांच हजार में तैयार हुई है । क्या उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट से रिक्वैस्ट की है कि मुझे भी लेटर आफ इंटेन्ट दिया जाये ? लेकिन चूंकि वह प्राइम मिनिस्टर का बेटा नहीं है इसलिए इसकी बात किसी ने नहीं सुनी ।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह तथ्य हैं कि आप कहते हैं कि कोई फारेन एक्सचेंज नहीं लिया जायेगा ? क्या यह भी तथ्य है कि फ्रांस की जो रेनू कम्पनी है उसके साथ आप ज्वाइंट वेंचर या कोलाबोरेशन कर रहे हैं छोटी कार के लिए और वह जो फ्रांस की रेनू मैंयुफैक्चरिंग कम्पनी है छोटी कार वाली उससे आपने तय किया है कि वे फ्री नो-हाऊ संजय गांधी को देंगे और उसके बदले में आप उनसे कोलाबोरेशन करेंगे ?

इसके अलावा जो एक मशहूर कहावत है :

> "Not only Caesar but also Caesar's wife should be above suspicion.

तो इस समय चूंकि सीजर और उसकी वाइफ दोनों ही सस्पिशन में हैं, अतः इस देश की नैतिकता के लिए और इस देश के लोगों के मन में जो भ्रम पैदा हो गया है कि भेद-भाव किया जा रहा है, क्या उस भ्रम को दूर करने के लिए आप वालन्टेरिली प्रधान मन्त्री से प्रार्थना करेंगे कि वे कहें कि मैं अपने बेटे को, चाहे वह उसका पात्र हो, तब भी लाइसेंस नहीं दूंगी ताकि जनता के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है उसको दूर किया जा सके ?...(**व्यवधान**)...

श्री दिनेश सिंह : जहां तक पहला सवाल है माननीय सदस्य का कि दिल्ली के किसी नवयुवक ने कोई पांच हजार की मोटर बनाई है, तो यहां पर मेरे पास जो कागज हैं उनमें उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है । ...(**व्यवधान**)... माननीय सदस्य ने खुद इसका जिक्र नहीं किया कि कोई लाइसेंस है या एप्लीकेशन हैं । उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पार्लमेंट के बाहर मोटर दिखा सकते हैं । अगर यह बजाय मोटर दिखाने के लाइसेंस दिखायें और इंडिजिनस नो-हाऊ अगर वे बनायेंगे तो मैं उस पर विचार कर सकता हूं । ...(**व्यवधान**)...जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमने फ्रांस की रेनू कम्पनी से तय किया है, कोलाबोरेशन के लिए तो हमारे पास जिन लोगों ने कोलाबोरेशन की दिलचस्पी दिखाई है उनमें से एक रेनू भी है ।

लेकिन हमने अभी फैसला नहीं किया है कि किसके साथ कोलाबोरेशन करेंगे ।

तीसरे जो माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या मैं प्रधान मंत्री से कहूंगा कि वे अपने लड़के से कहें कि वह लाइसेंस वापिस कर दें, मैं नहीं समझता कि यह एक सही कदम होगा । मैं समझता हूं कि जो नवयुवक हैं, चाहे वे श्रीमती इंदिरा गांधी के लड़के हों या किसी माननीय सदस्य के लड़के हों, अगर वे कोई चीज बना सकें तो हमको बड़ी खुशी होगी और हम उसमें मदद करेंगे ।...(**व्यवधान**)...

श्री रणधीर सिंह : स्पीकर महोदय, मैं आपकी मार्फत मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं क्या यह कोई जुर्म या पाप है चाहे वह मोरारजी का बेटा हो, रामसुभग सिंह का बेटा हो, श्रीमती तारकेश्वरी का बेटा हो या मधु लिमये जी का बेटा हो अगर वह काबिल हैं, होशिआर है, एन्टरप्राइजिंग है और उसमें इनीशिएटिव है, तो उसको मौका क्यों न दिया जाये ? मैं जानना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में कितनी एप्लीकेशंस आई थी और मधोक साहब ने जिसका जिक्र किया है क्या उसने भी अप्लाई किया था और उसके बाद क्या संजय साहब की कार की टेस्टिंग हुई ? मैं जानना चाहता हूं कि जिन्होंने चार-चार साल तक

मामूली मिकैनिक का काम किया टूटी फूटी वर्कशाप में उनका, भी कोई हक है या नहीं ? क्या यह सही है कि इसमें कोई कोलाबोरेशन का दरकार नहीं है ? क्या यह भी सही है कि इसमें कोई फारेन एक्सचेंज की दरकार नहीं है ? क्या यह भी सही है कि चार करोड़ से जहां पचास हजार गाड़ियां तैयार होंगी वहां दूसरी एप्लीकेशन्स में 8 करोड़ में 25 हजार गाड़ियां तैयार करने की बात कही गई थी ? तो जब इनका कोटेशन लोयस्ट था फिर क्या कारण हो सकता है कि दूसरे एप्लीकेन्टशस को लाइसेंस दिया जाता ? इन तमाम बातों की इत्तिला मैं आप से चाहता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितनी दर्खास्तें इस सम्बन्ध में आई थीं । हमारे पास इस सम्बन्ध में 10 दर्खास्तें आई थीं जिनमें से 8 दर्खास्तों में फारेन कोलाबोरेशन था या फारेन इम्पोर्ट था केपिलल गुड्स का । सिर्फ दो एप्लीकेशन्स ऐसी थीं जो इंडिजिनस नौ-हाऊ की बिना पर थी बिना इम्पोर्ट पर्चेज के और उन दोनों एप्लीकेन्ट्स को हमने लेटर आफ इंटेन्ट दिया है ।

SHRI H. N. MUKERJEE : May I know if the Minister agrees that, except in cases of extra-ordinary technical qualifications for a very special job, close relatives of such dignitaries as the Prime Mintster should be kept out normally of the ambit of such assignments because, otherwise, naturally there are unsavoury reactions in the public mind, embarrassment is caused to the individuals concerned and the public image of the country is, to a certain extent, tarnished ? If the Minister agrees that, except in the case of very extra-ordinary qualifications, this rule has to be observed, may I know if in this particular case we can be told about any extraordinary technological qualifications or any facilities available to the individual concerned which made it incumbent on the Government to depart from the practice not only dictated by democratic practice but by commonsense ?

SHRI DINESH SINGH : I would agree entirely with the hon. Member that we should not show any special favour or concession in case of (*Interruptions*). I was saying, Sir.....(*Interruptions*). I must also have an opportunity to express my views. since I have heard the views of the hon. Members.

Now I was saying that I would entirely agree with the hon. Member when he says that we should take extra care to see that there is no special favour or concession shown.....(*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Will you kindly listen to him ? You must have some patience.

SHRI DINESH SINGH : Now even at the pain of repeating myself, I am compelled to do so to say that I would entirely agree that we should show no special favour or concession in case not only of the Prime Minister's son but also of any other Minister or hon. members. But the point here is that if there is somebody who is wanting to do something in this country..... (*Interruptions*).

SHRI RANGA : Sir, let him give a straight answer. He is burking the issue.

SHRI DINESH SINGH : I shall come to everything provided the members want to listen to me. If they want to go by their own views, then let us move on to some other question.

All that I was trying to say is that this that it is...(*Interruption.*) I shall be glad to give a licence to Achrya Rangaji for a shock absorber if he wants.

So far as the question we are dealing with here is concerned, it is not a question of showing extraordinary qualification. I ask the hon. Member to tell me why a person who is capable of a doing something, whether it is a question of seeking employment, or it is a question of doing something, why should be he prevented from taking part in the economic life of our country

just becanse he happens to be the son of some Minister (*Interruption.*) No. It would be quite wrong in my opinion (*Interruptions.*) I was saying that in my opinion it would be quite wrong for the son of a Minister to be a hanger-on and try to get money from other sources. He must do on honest job and if he can do an honest job, why should he be prevented ? (*Interruption.*)

श्री तुलशीदास जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हांलाकि यह स्मौल कार का सवाल मेरी समझ में कोई पिछले 7-8 साल से चल रहा है और क्या यह सच नहीं है कि अभी तक किसी भी कार मैनुफैक्चरर ने भारत सरकार को खुद यहां के इंडिजनस पार्टस से कोई वैसी कार बनाने की योजना नहीं बताई है ?

क्या यह सही नहीं है कि श्री संजय गांधी ने यहां के इंडिजनस पार्टस से चार कारें बनाई जिनमें से दो कारें उन्होंने गवर्नमेंट को बतलाई और गवर्नमेंट ने उन्हें मंजूर किया और क्या यह बात भी सही नहीं है कि अन्य किसी कार बनाने वाले ने वैसी कार सरकार को नहीं बतलाई जोकि इतनी कम कीमत की हो जिसकी कि कौस्ट 6000 तक हो और अब यदि कोई व्यक्ति वैसी कार गवर्नमेंट को बना कर दे सकता है जो कि सब से कम कीमत की हो और इंडिजनस पार्टस की हो, तो क्या वह व्यक्ति अगर ग्राम सेवक से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के स्तर के किसी पदाधिकारी का लड़का या रिश्तेदार होगा तो उसका पात्र होने पर भी उसे उसका लाइसेंस नहीं दिया जायेगा और क्या ऐसा करना सरकार के लिए न्याय संगत होगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी कहा कि हमारा इरादा नहीं है कि हमारे जो नियम आदि के अनुसार उस काम को कर सकता हो उसे करने से रोकें । वह चाहे किसी का भी लड़का हो जो भी नियम के अनुसार उस काम को करने की क्षमता रखता हो उसे सरकार लाइसेंस देगी ।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. SPEAKER : The question has already taken 45 minutes.

SHRI PILOO MODY : Another 15 minutes may be given.

श्री कंवर लाल गुप्त : श्री पीलू मोडी तो छोटी कार में बैठ भी नहीं सकते हैं उन्हें सवाल पूछने क्यों दिया जा रहा है ?

SHRI S. M. BANERJEE : MR. Piloo Mody should not be allowed to put a question on small car project.

MR. SPEAKER : He can sit in a small car. Mr. Piloo Mody can sit in a small car provided it has only one door.

SHRI PILOO MODY : I would like to know why this proposal has not been submitted in a more honest fashion. This project has been given the licence. There are a large number of units which manufacture the components.

Every such unit will utilise a substantial portion of foreign exchange content. This foreign exchange content should be debited to this particular small car project, and not tosomebody else's project, not to some other importer, not to some other manufacturing company but to this particular company. The Minister has reiterated for the seventeenth time that these were the qualifications required from a particular applicant. He mentioned, no collaboration ; no foreign exchange. And yet, the position is this : The car will contain a substantial percentage of foreign exchange which, I say, 'dishonestly' has been moved away from this project and has been placed in another project. There are units of shock absorbersuor horns or springs or starters and many other things which are required. After all, he will have to purchase these things from the market, from the people who manufac-

ture these particular items. And, when those people apply for licences, they will be given priority over other users, because, this prticular project is being started by Sanjay Gandhi. So, I want to know clearly and categorically from the hon. Minister as to the exact quantum of foreign exchange which this project will utilise. That is my first point.

Secondly, it is a remarkable coincidence that the sons or relatives of every Minister just happens to have a project which fits in with Government's pattern. There are thousands of other applications which never see the light of day.

SHRI DINESH SINGH : In his usual manner, the hon. Member Shri Piloo Mody has tried to present the case from the wrong end. The question here is this:

SHRI PILOO MODY : What he meant by the wrong end was this end. Let him present it from his end, Sir.

SHRI DINESH SINGH : Very soon the House will have an opportunity to see which end the hon. Member used. So far as the particular question of parts and components is concerned, when I gave out the percentage of foreign components, the hon. Member being very well in with the private sector, knows very well that the percentage of these Parts .....*(Interruption)*.

SHRI PILOO MODY: Can I make an allegation that he is very well in which the other people, that is Mrs. Indira Gandhi and her son ? I do not accept these allegations which he has made. Let him not resort to Mr. Chavan's cheap jibes.

SHRI DINESH SINGH: I belong to the public sector ; I am in with the public sector.

So far as these percentages are concerned, as percentages of the total car, they are very very small. Take the present cars that we are manufacturing in this country, which are also using these parts and components. Take the Fiat, for instance, which is in the private sector, and which is being manufactured here without any fuss, and which is also using these parts. They have over 99 percent of indigenous material ; therefore, when you add this up over the total product of the car, this will roughly come to the same. Therefore, although the percentage of the horn as such to which the hon. Member had made a reference may appear 5 per cent or may appear to be too much, when it is taken on into the overall cost of the car, it will come to a fraction of the percentage. Therefore, this was the whole point in talking of an indigenous car.

The House is well aware that today we are now working industry and commerce in a phase of a certain measure of interdependence. Even the most developed countries do not find it advantageous to manufacture each single part themselves. The export some parts and import some parts. We are also exporting parts and components; we are also importing certain essential raw materials that go into it. Therefore, this is part of international commerce which has developed. Therefore, the picture that the hon. Member was trying to project that if you add up all this, this will form a major part of the cost of the car is totally unfounded.

SHRI PILOO MODY : I want to know how much it will be.

SHRI DINESH SINGH : It will be a very insignificant part.

SHRIMATI SHARDA MUKERJEE : I have tabled another question on the same subject. I may be permitted to ask one supplementary question.

MR. SPEAKER : This has taken mroe than fifty mintues. I think some consideration is due to the other questions also. They are also good questions.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : But we have taken up two questions together. Already, so mueh time has been devoted to them.

MR. SPEAKER : His party did not get a chance. So, he can have it now.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY: In the statements laid on the Table of the House there is no mention of any company, either public limited or private limited, on behalf of which Shri Sanjay Gandhi had applied for a licence. Probably, it is a proprietary coneern. If that is so, are Government satisfied that Shri Sanjay Gandhi has the financial capacity to have such a big project, and if not, will they spell out and let us know what his finaacial capabilities are.

SHRI PILLO MODY : Unlimited.

SHRI SURENDERANATH DWIVEDY: Since he has stated that he will do it with indigenous support, may I know whether any indigenous capitalists or monopolists in the country are going to finance this project? The hon. Minister has stated that because one happens to be a Minister's son, one should not be left in the streets. But is it not a fact and has it not been the desire of his House, which I think was also one of the main recommendations of the Santanam Committee that during the term of office of a person who is a Minister or who is holding any such auth ority, his family members should not have any business transactions, relations, or trade with Government ? May I know whether when the Licencing Committee recommended this and the Cabinet sanctioned this, this aspect was considered by the Cabinet, and whether the Cabinet has decided that henceforward if they find that the relations or family members of people who are closely connected with the Ministers who know the internal administrative technicalities apply for snch projects with greater detail and in a more knowledgeable manner, than others, they will be entitled and naturally they will have precedence over others, and Government will be free to give them licence ? I want a categorical answcr.

SHRI DINESH SINGH : So far as the financial arrangement is concerned, I understand that Shri Sanjay Gandhi intends to float a public limited company to raise finances and manufacture this car.

SHRI HARDAYAL DEVGUN : There is no company so far. He will float one.

SHRI DINESH SINGH : Only a letter of intent has been issued, not a licence. Before a licence is issued, it is expected that Shri Gandhi will float a public limited company and will also be able to present a model to us for inspection so that we can see its roadworthiness.

Regarding the details the hon. member mentioned about the Santhanam Committee's Report, I think these have been discussed and whatever guidelines and other things had to be adopted have already been considered.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : No, no.

MR. SPEAKER : I must give at least five minutes to the next question.

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY : Let him relpy to my question. About the other proportion, probably he does not want to answer and I am not insisting on it, but let him at least clarify this point as to whether before a letter of intent is issued, the financial capability is ever considered. Do I tkae it that the financial resources are not taken into account ?

SHRI JYOTIRMOY BASU : Will a parliamentary committee be constituted to inquire into this matter ?

MR. SPEAKER : Next question.

Death of a Railway Employee in an Accident near Saiyad Sarawan (Northern Railway)

*32. SHRI JHARKHANDE RAI :
SHRI V. NARASIMHA RAO :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the driver and the Assistant Driver of a goods train were killed in an aecident on the 3rd October, 1970 near Saiyad Sarawan railway station on the Allahabad-Kanpur section of the Northern Railway ;